allotted time for Government legislative and other business as follows:

1. Statutory Resolution seeking disapproval of the Special Court (Trial of Offences relating to Transactions in Securities) Ordinance, 1992 (No. 10 of 1992)	2 Hrs. (To be discussed together)
2. Consideration and passing of the Special Court (Trial of Offences relating to Transactions in Securities) Bill, 1992, after it is passed by the Lok Sabha.	
3. Consideration and passing of the following Bills, after they are passed by the Lok Sabha:—	
(a) The Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 1992.	2 Hrs.
(b) The National Highways (Amendment) Bill, 1992.	1 Hour.

The Committee recommended that the House should dispense with the Lunch Hour during the remaining part of the current Session, and sit as late as possible.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Before we take up half-an-hour discussion, I must bring to the notice of Mr. Abrar Ahmed and Shri K. L. Sharma and other Members that half-an-hour means that you make short speech and if anybody wants to ask a question, he can do so but there should be no speeches on it and it should finish in half-an-hour.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Points arising out of the answer given in the Rajya Sabha on the 6th August, 1992 to Starred Question 422 regarding Foreign Secretary Level talk between India and Pakistan

डा० अबरार अहमद : (राजस्थान) : थैंक यू, मैडम । मैडम, जहां भारत और पाकिस्तान की वार्ता के संबंध में या वर्ता के जरिए से किसी हल्के संबंध में बात आती है तो मैं इस संबंध में एक शेर कहना चाहता हूं :

"हमको उनसे है वफा की उम्मीद,
जो नहीं जानते वफा क्या है ।"

उपसभापति महोदया, कोई भी बातचीत हो उसके अंदर बातचीत करने वाले की नीयत क्या है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है । अगर नीयत साफ है तो यकीनी तौर से बातचीत साफ होगी और उसके रिजल्ट साफ होंगे, लेकिन अगर बातचीत तो कर रहे हैं और नीयत खराब है तो मैं यकीनी तौर से कह सकता हूं कि उस बातचीत का कोई अर्थ निकले ऐसा मैं मानकर नहीं चलता । नीयत सही है या गलत, इसका पता कैसे लगे ? इसका सीधा तरीका है कि अगर हम पास्ट को देखें या पहले जो बातचीत हुई हो उसको देखें कि किस प्रकार की बातचीत हुई और उसके क्या परिणाम निकले । तो मैं समझता हूं कि नीयत का पता लगाना बहुत आसान है ।

महोदया, इस संबंध में माननीय मंत्री जी को याद होगा कि 30/31 अक्तूबर को इसी स्तर की वार्ता हुई थी, सचिव स्तर की वार्ता इस्लामाबाद में हुई थी और उस वार्ता के अंदर हमारे विदेश मंत्रालय के उस समय के सचिव मुचकुंद दुबे जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया । वार्ता के बाद बड़े प्रसन्न रूप से उन्होंने इस्लामाबाद से रवाना होते समय पत्रकारों को कहा कि वार्ता बहुत ठोस हुई है और इसके बड़े सकारात्मक परिणाम निकलने वाले हैं । उनके आने के दो दिन बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत से हमारे संबंध तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक कि कश्मीर का मसला वहां की जनता की इच्छानुसार कोई न्यायसंगत तरीके से हल नहीं हो जाता । ठीक उसके दो दिन बाद यानी 4 नवंबर को पाकिस्तान के राष्ट्रपति गुलाम इशाक खां ने युरोपीय संसद संसद से कश्मीर के लोगों को स्वायतता का अधिकार दिलाने में सहयोग का आग्रह किया ।

नौ सदस्य, एक संसदीय दल पाकिस्तान गया हुआ था और ठीक उसके दो दिन बाद यह कहा गया और फिर उसके दो दिन बाद रामजन्म-भूमि और बाबरी मस्जिद के बारे में इस्लामाबाद में एक बयान दिया गया। अगर इन सब बातों को हम देखें कि किस प्रकार से पहले की हमारी सचिव स्तर की वार्ता हुई, उसमें सचिव महोदय क्या इम्प्रेशन लेकर आए और वहां से क्या बोले और फिर उसके दो-दो दिन बाद किस-किस प्रकार के डवलपमेंट हुए तो उससे मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की नीयत के बारे में हमें कुछ सोचने की आवश्यकता रह जाती है या उसकी नीयत का अंदाजा लगाने की आवश्यकता रह जाती है।

महोदया, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान बार-बार जो वार्ता की बात करता है, उसका उद्देश्य बहुत सीधा है। वह वार्ता के माध्यम से भारत को उलझाए रखना चाहता है और अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। हमें उलझा कर पाकिस्तान हमारे यहां आतंकवाद को हवा देते रहना चाहता है कि बातों के जरिए उलझाए रखो और आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखो, जो इल्लीगल अस्त्र-शस्त्र देते हैं उनको बराबर जारी रखो।

महोदया, दूसरा जो उसका लक्ष्य है, वह लक्ष्य बहुत सीधा है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय महत्व वह अपना खो चुका है। हम इस बात को नहीं कह रहे हैं बल्कि जो उनके पारंपरिक समर्थक देश अमरीका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस है, वे यह स्पष्ट कर चुके हैं कि जो भारत के अन्दर कश्मीर और पंजाब में आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं, पूरे तरीके से वह गतिविधियां पाकिस्तान की शह पर चल रही हैं। बातचीत का यह ढोंग वह आज से नहीं बल्कि बहुत दिनों से चला रहा है, चाहे चन्द्रशेखर जी की जब सरकार थी तो हॉट-लाइन पर उनको यह बात कहते हों कि हम बातचीत के जरिए से सुलझाना चाहते हैं या हमारे माननीय प्रधानमंत्री से हरारा में जब बात हो तो यह बात कहते हों बात बराबर कहते हैं, लेकिन भारत को जर्क देने में, नुकसान देने में कहीं किसी कीमत पर वह चुकना नहीं चाहते।

तो, महोदया, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं और जैसा मैंने अभी कहा कि उनके जो पारंपरिक समर्थक देश हैं, उन्होंने भी अपनी बात कही है। मैं अपनी बात नहीं कहता, बल्कि लंदन में 30 नवंबर को ब्रिटेन सरकार में हाऊस आफ कॉमन्स में विदेश एवं कॉमनवेल्थ राज्यमंत्री टी. जी. जोन्स ने कहा—"पंजाब में सिख मिलिटेंटस पाक के प्रशिक्षण हुए शस्त्रों के रूप में समर्थन का दम भरते हैं। हम पाक सरकार से आग्रह करते हैं कि वह इस मामले में समर्थन से परहेज करे।" इसके साथ ही साथ श्री जोन्स ने कहा—"मिलिटेन्सी ने भारत की वैधानिक एकता को खतरा पैदा कर दिया है। इस रास्ते पर चलने वाले लोग पूरे सिख समुदाय पर कलंक हैं।" उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय व जल विवाद जैसे मामले लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हल किए जाने चाहिए न कि अपहरणों, गोलियों और बम के धमाकों से। उन्होंने कहा कि इस संकट का भारत सरकार साहसपूर्ण मुकाबला कर रही है तथा हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। उन्होंने सदन को बताया कि भारत सरकार मानती है कि कुछेक मामलों में मानव अधिकारों का हनन हुआ होगा, भारत सरकार ने ऐसे हनन के मामले पता लगने पर कार्रवाई भी की है तथा दोषी 89 पुलिसकर्मियों और 79 अन्यों को सेवा से बर्खास्त किया है एवं 68 को समय से पूर्व सेवा-निवृत्ति दी है। उन्होंने कहा कि सिख मिलिटेंट्स की गतिविधियां अब केवल भारत तक ही सीमित नहीं, बल्कि अब यहां ब्रिटेन में भी फैल रही हैं। यहां कुछ लोग उनको समर्थन देते हैं, पर हम इस बात की कदापि अनुमति नहीं देते। जो ब्रिटेन में रहते हैं तथा भारतीय सिखों का समर्थन करते हैं, उनको एक बात समझ लेनी चाहिए कि जब तक वे हिंसा की भर्त्सना नहीं करते, उनका कोई काम नहीं होगा।" तो यह बहुत स्पष्ट है, मैंने एक ब्रिटेन का उदाहरण यहां दिया, लेकिन इस प्रकार के शब्दों में और भी देशों ने पाकिस्तान को साफ रूप में चेतावनी दी है और यह माना है कि जो आतंकवाद हमारे देश में चल रहा है, उसके पूरे सबूत हैं और उसके अंदर पाकिस्तान का पूरा हाथ है। आज चाहे हमारे पंजाब के अंदर

आतंकवाद हो, कश्मीर में हो, यू० पी० की तराई में हो या असम में हो, इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि पाकिस्तान का उसमें हाथ है। महोदया, मैं इस अवसर पर यह भी बताना चाहता हूं कि 20 हजार व्यक्तियों को "केट्" नामक योजना के अंतर्गत पाकिस्तान के अंदर प्रशिक्षण दिया गया है, जो आज भारत की विभिन्न सीमाओं के जरिए से भारत में प्रवेश करके आतंकवाद फैलाने की तैयारी कर रहे हैं और आज हमें उन लोगों से बड़ी सतर्कता से निबटना होगा। महोदया, एक बहुत गौरतलब बात है कि आखिरकार कश्मीर की हालत किसने खराब की है ? जो बेगुनाह लोग आज वहां मर रहे हैं, उन्हें कौन मार रहा है ? जो बेगुनाह लोग आज वहां से भाग-भाग कर आ रहे है, उन्हें कौन भगा रहे हैं ? पाकिस्तान कश्मीर की हिमायत करता है, लेकिन क्या यह उसकी हिमायत है कि जिसने उस कश्मीर को, जो शांति से जी रहा था, एक नर्क बना दिया है और उन कश्मीरियों को मरने के लिए मजबूर कर दिया है ? तो यह उन कश्मीरवासियों को भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान उनका हिमायती नहीं है बल्कि पाकिस्तान ने कश्मीर-वासियों के साथ एक जघन्य अपराध किया है जिसके कारण आज वे अपने घर से बाहर हैं, वहां रह नहीं सकते, शांति से जी नहीं सकते, हर दिन उन्हें गोलियों की आवाज के बीच में रहना पड़ता है, हर सुबह उठने के बाद उन्हें पता नहीं होता कि उनकी शाम कैसी होगी और सुबह कैसी होगी।

महोदया, भारत के अंदरूनी मामलों की जहां तक बात है, उसके मुझे यहां पर उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान भारत के अन्दरूनी मामलों में किसी भी मसले पर किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप करने से नहीं चुकता है। अभी हाल ही में, मैंने अभी भी कहा, पहले भी, कि नवम्बर के अंदर जब हमारी सचिव स्तर की वार्ता हुई, उसके ठीक चार दिन बाद उन्होंने बाबरी मस्जिद के बारे में बयान दिया और अभी 15 दिन पहले फिर उसी पाकिस्तान ने राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद के बारे में बयान दिया। क्या हक पहुंचता है उसको भारत के अंदरूनी मामलों पर बोलने का जो पाकिस्तान अपना नहीं संभाल सकता, अपनी बात नहीं कर सकता ? अरे यह तो वह हिन्दुस्तान है जिसने 1947 के बाद जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके संबंध में इसी सदन के अंदर श्री नरसिंह राव जी के नेतृत्व में एक बिल लाया और यह स्पष्ट कर दिया कि भारत एक डेमोक्रेटिक देश, सब धर्मों की रक्षा करने वाला देश है। वह पाकिस्तान आज हमें नसीहत दे कि कैसे चलना है, क्या करना है –कभी राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद के बारे में कहे और कभी किसी और बारे में। इस संबंध में जो टैरेरिस्ट एक्टिविटी वह चला रहा है, इस संबंध में मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जो एक हजार अफगान मुजाहिदों को विध्वंसकारी हथियारों के साथ भारत की सीमा में घुसाने का प्रयास है उसका, वह बहुत ही खतरनाक है। जनरल युसूफ की पुस्तक के अनुसार उनके पास जो हथियार हैं उसमें एक हजार रासायनिक और इलेक्ट्रानिक बम, सी०आई०ए० द्वारा अफगान मुजाहिदों के लिए तथा सी–4 प्लास्टिक विस्फोटक बम तथा ऐसी गनें हैं जो ए०के०–47 से भी ज्यादा क्षमता रखती हैं और जो रात्रि के अंदर रात्रि दृष्टि संयंत्र के माध्यम से चलती हैं। तो ऐसे खतरनाक संयंत्रों के माध्यम से, हथियारों के माध्यम से अफगान मुजाहिदों को वह भारत की सीमा के अंदर प्रवेश कराना चाहता है। महोदया, मैंने इस संबंध में जो वार्ता की बात करते हैं और यहां जिनके बारे में वार्ता हम करने जा रहे हैं, उस बारे में कहा था कि 11 जुलाई को पाकिस्तान के प्रधान मंत्री नवाज शरीफ ने ढाका के एक समाचार-पत्र "डेली स्टार" को दिए गए बयान, जिसमें भारत पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए यह कहा कि कश्मीर विवाद के रहते हमारे संबंध नहीं सुधर सकते। इतना ही नहीं उन्होंने दिल्ली को एक सलाह दी और वह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने नई दिल्ली को सलाह दी है कि वह हथियारों का उत्पादन छोड़ दें और अपने धन का उपयोग उन 80 करोड़ लोगों के कल्याण के लिए करें, जो गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूं कि

धन को सैनिक तैयारी में लगाने, अधिकाधिक लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों, मिग-29 और टैंकों की खरीद में लगाना अनुचित है। अनुचित इस रूप में कि लोगों को उस धन से वंचित किया जा रहा है जिसका उपयोग उनके लिए किया जा सकता है। यह 11 जुलाई को उन्होंने कहा है। क्या यही बात करने वह भारत आ रहे हैं? क्या उस वार्ता में यही बात वह यहां रखने वाले हैं। माननीय उपसभापति महोदया, क्या हक पहुंचता है हमारे देश के अंदर कौन क्या है? लेकिन जो भी हैं उनसे हम लाख दर्जे अच्छे हैं। हमारे देशवासी उनसे हर हालत में अच्छे हैं। हमें किस पर खर्च करना चाहिए, किस पर नहीं खर्च करना चाहिए, यह उनसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही पूछना चाहता हूं कि जब इस प्रकार के विचार पहले से वह बहुत ओपनली दे रहे हैं, कह रहे हैं, तो हमने वार्ता के लिए अपनी क्या तैयारी की है। तथा वहां बैठकर भारत को जो नसीहत और सलाह देना चाहते हैं, तो उनके साथ बातचीत करने के लिए हमने क्या तैयारी की है और इन बातों का हम उनको क्या जवाब देने जा रहे हैं? इतना ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अन्दर हमारे दूतावास में जो लोग हैं तथा वहां जो एक मित्तल कार्यरत थे, उनका अपहरण करके जिस प्रकार उनके साथ ज्यादती की गई, तो वह क्या उन नियमों के तहत है जो इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय नियम बने हुए हैं? माननीय उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी लेना चाहूंगा कि इसके अंदर क्या पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था? जो लोग, बल्कि मुझे तो जहां तक अखबारों से पढ़कर पता लगा है, यहां तक इस चीज की जानकारी मिली है कि वहां पर पाकिस्तान सरकार के जो सिपाही तथा और लोग पहरे पर लगे हुये थे, उन्हीं ने उनका अपहरण किया था। तो क्या यह भी इस वार्ता में सम्मिलित करेंगे? यदि हमारे दूतावासों के लोगों के साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार किया जाएगा तो क्या हमारे राजनयिक सम्बन्ध किसी से बने रहना उचित होगा?

महोदया, इतना ही नहीं, जो यहां राडू का अपहरण हुआ था, के संबंध में भी माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह अपहरण किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से उसको छोड़ा गया? इस अपहरण के अन्दर भी निश्चित रूप से आतंकवादियों का हाथ था और उन आतंकवादियों का हाथ था जो पाकिस्तान से आए हुए हैं या पाकिस्तान से मिले हुए हैं। क्योंकि उसको तब छोड़ा गया जब पश्चिमी देशों का पाकिस्तान पर दबाव पड़ा कि उसको छोड़ा जाए और तभी वह छूटा। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि भारत के अंदर राज दूतावासों में जो विदेश के लोग काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की शह पर जिनका अपहरण करके यातनाएं दी जाती हैं, क्या यह भी इस वार्ता में सम्मिलित करेंगे और इस सम्बन्ध में भी क्या पाकिस्तान को चेतावनी दी जाएगी कि भारत के अंदर वह जो आतंकवादी गतिविधियां फैला रहे हैं, उसको समाप्त करे।

उपसभापति महोदया, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

उपसभापति : मंत्री जी, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं दूसरे लोगों से सवाल कराऊंगी।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : वैसे यहां कौमन सवाल ही होंगे। मेरा ख्याल था कि सभी बोल लेते तो मैं एक ही बार में जवाब दे देता।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : प्रोसीजर ही यह है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: This is the procedure.

श्री आर०एल० भाटिया : जैसा आप कहें।

उपसभापति : पहले आप बोल दीजिए, Then they will ask.

श्री आर०एल० भाटिया : मैडम, अबरार जी ने दो बातों की तरफ ध्यान दिलाया है। एक तो यह कि पाकिस्तान के लीडर बात कुछ करते हैं और उनके मन में कुछ और बात होती है। उन्होंने काफी बातें बताई जो पाकिस्तान कर रहा है, चाहे वह हमारे मामले में दखल दे रहा है, चाहे वह राम जन्म भूमि का मामला हो, चाहे वह कश्मीर का हो या अन्य मामला हो, उसमें पाकिस्तान हस्तक्षेप कर रहा है। दूसरा सवाल उन्होंने यह किया कि जब उनकी तरफ से ऐसी बात की जा रही हैं तो फिर जो दोनों देशों के सैक्रेटरी के दरम्यान जो बातचीत होनी है, तो फिर इस बातचीत का क्या मायना है और उसमें क्या-क्या बातें यह करने जा रहे हैं? मैं आनरेलिब मेम्बर साहब को यह बात बताना चाहता हूं कि यह एक लगातार बातचीत का सिलसिला चल रहा है। इससे पहले भी पांच मीटिंग हो चुकी हैं और उसके बाद यह मीटिंग हो रही है, जिसमें हमारे कामन मसले हैं, उनको हम जेरे-बहस लायेंगे। वैसे तो इस बातचीत का कोई एजेंडा नहीं है खुली बातें है। क्या बातें वह करेंगे, क्या सवाल हम उठायेंगे, यह एक खुला एजेंडा है। इसमें हरएक बात हो सकती है। लेकिन जो मेन मुद्दे हमने उनके सामने रखे हुए हैं उसका उनको जवाब देना है। जैसे कि आपने डिप्लोमेट का जिक्र किया कि वहां हमारे डिप्लोमेट पर अटक हुआ। जब यह बातें हुई तो हमने उनको प्रोटेस्ट किया तथा उसके बदले पाकिस्तान के जो दो यहां डिप्लोमेट थे, उनको वापिस भेजा तो उनकी तरफ से यह बात आई कि डिप्लोमेट के बारे में एक कोड बनाया जाए। तो उन्होंने वह हमको प्रपोजल भेजे हैं और हमने उनमें कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं और उनका जवाब भी मीटिंग में मिलेगा। तो डिप्लोमेट्स के बारे में जो भी हमने कायदा बनाना है वह इस बातचीत में शामिल होगा और दूसरी बात जो आपने कही है कि हमारे इलाके में वह हस्तक्षेप करते हैं बयान देते हैं कभी राम जन्म-भूमि और दूसरी बातों के लिए, इन बातों पर हमने उनको बता दिया है कि यह हस्तक्षेप है हमारे मामले में और इस बात को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये सारी बातें जो आपने कही हैं, इसका जवाब हम मीटिंग में देंगे और पुरजोर अलफाज में हिन्दुस्तान का जो नक्ते-नजर है, उनके सामने रखेंगे।

उपसभापति : कृष्ण लाल जी, आप बोलिये, आपका नाम है इसमें।

श्री कृष्ण लाल शर्मा (हिमाचल प्रदेश) : महोदया, यह जो चर्चा है इसमें पहले मेरा नाम था, आपने मंत्री जी को पहले बोलने को कहा। मैं इस संबंध में कुछ बातें पूछना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी उसका जवाब देंगे। अबरार अहमद साहब ने अपनी बात एक शेर से शुरू की थी। मैं भी उसी तरह शेर से शुरू करना चाहता हूं –

"अब अगर जख्म मिले हैं तो शिकायत कैसी,
हमने पत्थर के खुदाओं की इबादत की है"

महोदया, मैं यह पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का आधार क्या है? इस वक्त कोई भी बात अपने सामने स्पष्ट न होते हुए भी हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो क्या यह बातचीत कोई कर्मकांड है कि साल में दो-तीन बार हमको बात करनी ही है या हमने गीता से यह सीख लिया है कि निष्काम भाव से बात करनी है, कोई नतीजा निकले या न निकले। हम बात करते चले जायेंगे।

मंत्री जी यह भी कह दिया कि खुला एजेंडा है। मैं तो इससे सहमत नहीं हूं। अगर हमने उनसे बात करनी है तो उसके लिये निश्चित रूप से स्पष्ट विषय चाहिये। हमारी कुछ बातें हैं उनका उल्लेख होना चाहिये। आप यह खुला अजेंडा की बात कहकर अपने देश को भी अंधेरे में रखना चाहते

[श्री कृष्ण लाल शर्मा]

है और उनको भी कोई बात नहीं कहना चाहते हैं । उसके बाद हालत यह है कि इतनी बातें सेक्रटरी लेवल पर हुई । हमारे प्रधानमंत्री जी रीओ गये । राजीव गांधी जी के समय में बेनजीर भुट्टो आई तो उन्होंने प्रमाणपत्र दे दिया कि ये अब आई है तो बड़ा अच्छा माहौल हो गया है । अब नया वातावरण बनेगा, नया चैप्टर खुलेगा । फिर थोड़े ही दिनों में डिसइल्लयूजन हो गया और कहने लगे कि ये तो उसी रास्ते पर है । हमारे चार-चार प्रधानमंत्रियों ने बातें की हैं । एक प्रधानमंत्री तो हाट लाइन पर आ गये थे और उन्होंने यही घोषणा कर दी कि हमारे इतने अच्छे संबंध हैं कि अब तो हाटलाइन पर हम बात करते हैं और जिस समय भी कोई समस्या होती है, तब हम बात करते हैं ।

मुझे यह कहना है कि क्या किसी बातचीत का कोई अनुकूल परिणाम निकला है ? किसी भी बात का, चाहे वह सचिव लेवल पर हो, चाहे प्रधान मंत्री लेवल पर हो । इसके विपरीत स्थिति यह है कि हमारे प्रधानमंत्री से उन्होंने रीओ में बात की, डवोस में बात की लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया ? उसके बाद उन्होंने आफिशियली यह घोषणा कर दी कि हम "कश्मीर डे" आब्जर्व करेंगे और सारे पाकिस्तान में हड़ताल करेंगे ।

जब आप मंत्री लेवल की बात करते हैं तो मैंने इसमें कहा कि कोई तो आधार होना चाहिये । आपने इससे पूर्व मंत्री लेवल की तीन जून को होने वाली बातचीत स्थगित कर दी, इसलिये कि राजेश मित्तल से उन्होंने दुर्व्यवहार किया । उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि वे रीओ जा रह है, और वहां 14 जून को प्रधान मंत्री नवाज शरीफ से बात करेंगे इस बीच पाकिस्तान ने श्रीवास्तव से दुर्व्यवहार किया और इसके बावजूद आप कह रह है कि हम उनसे बात करेंगे । तो आखिर इसमें हमारी क्या मजबूरी है ? क्यों हम बात कर रहे हैं । जब भी कभी मंत्री लेवल की बात होती है, कोई न कोई घोषणा नवाज शरीफ जरूर करते हैं । अभी भी आप बातचीत कर रहे हैं तो उन्होंने घोषणा की है कि हम कश्मीर को लिबरेट करायेंगे और वह दिन दूर नहीं है जब हम वहां जायेंगे । यह घोषणा वे करेंगे और आप फिर भी बातचीत करेंगे । इसके बाद गवर्नर की रिपोर्ट है कि बार्डर पर उनका दबाव बढ़ रहा है, वह अपनी फौजें ला रहे हैं और अपना दबाव बढ़ा रहे हैं । वह पाक आक्यूपाइड काश्मीर में अपने ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं । वह हमारे इलाके में इंट्रूजन कर रहे हैं । सियाचीन के बारे में रिपोर्टस है कि हमारे इलाके में आकर उन्होंने हस्तक्षेप किया, अंदर जाकर घुस गये हैं । पहले पंच एरिया में घुस गये थे । उनको वहां से निकाला । ये सब कार्यवाहियां बढ़ती जा रही हैं और हमारी प्रतिक्रिया क्या है ? हम प्रतिकार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रतिक्रिया भी मजबूती से व्यक्त नहीं करते है और हम उनको सर्टिफिकेट देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री उनको प्रमाण पत्र देते हैं यह कहकर कि वहां माहौल अच्छा हो रहा है । हम पूछना चाहते है कि क्या इन सारी पिछली बातों में से एक भी पाजिटिव बात अपने पक्ष में आप मनवा सके हैं ? क्या उन्होंने आतंकवादियों को मदद देना बन्द कर दिया ? क्या सीमा पर घुसपैठ करना बन्द कर दिया है ? हमारी बताई हुई किसी बात को उन्होने स्वीकार किया है ? मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि हम दोबारा उसी गलती को दोहरा रहे हैं । एक गलती हमने की थी । हिन्दी चीनी भाई भाई के नारे लगाते रहे और चीन हमारे पड़ौसी तिब्बत को खा गया । हम पाकिस्तान से बातचीत करते जा रहे हैं लेकिन उन्होंने पहले अफगानिस्तान पर अपना दबाव जमा लिया है और फिर अफगानिस्तान से मुजाहिदों को साथ लेकर काश्मीर पर दबाव डाल रहा है । हम 9 अगस्त को क्विट इंडिया डे मना रहे हैं, हमने क्यों नहीं घोषणा कर दी "क्विट अवर काश्मीर" ? क्यों हम अपनी कोई

प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकते है मेने क्विट इंडिया डे पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की । हमने दोनों हाउसज में 1962 में यह रेजूलेशन पास किया था कि हम अपने देश की एक-एक इंच भूमि को खाली करवायेंगे ? क्या उस संकल्प पर हमारी सरकार कायम है ? क्या आप आश्वासन देते हैं कि ह हर कीमत पर काश्मीर को लेंगे क्योंकि अब संदेह व्यक्त हो रहे हैं कि लाइन आफ कंट्रोल पर समझौता करने की भी मानसिकता आप बना रहे हैं । मेरा कहना है कि कुछ बातें आपको स्पष्ट करनी चाहिये ।

महोदया, विषय सूची और वातावरण ठीक बनाये बिना आप बातचीत करने के लिये जायेंगे तो इसको हमारी कमजोरी माना जायेगा । सारी बातें हजम करने के लिये जाते हैं, तो यह अच्छी बात नहीं है । इसमें हमारा अपमान होता है । हमारा छोटा देश नहीं है, 86 करोड़ की संख्या का विशाल देश है । जब-जब लड़ाई हुई है, हमने उनको मुहतोड़ जवाब दिया है । क्यों हम अपमानजनक बातें सह रहे हैं ? हमारे डिप्लोमेट्स का वह अपमान कर रहे हैं । हमारे प्रधान मंत्री किसी बात पर रेस्पांड नहीं करते हैं । कोई भी बात उन्होंने ऐसी कही है कि आप काश्मीर में हमारे इलाके में, पंजाब में, हर जगह हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं ? इसलिये मैं फिर वही निवेदन करूंगा कि कोई भी बात निश्चित सूची के बिना करना, ऐजेंडा निश्चित किऐ बिना करेंगे तो इसे हमारी कमजोरी ही माना जायेगा । अगर मीटिंग की है, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री कोई बयान देते हैं, तो हमें कोई मीटिंग नहीं करनी चाहिये । हमें स्पष्ट कर देना चाहिये कि यह आपका रवैया है तो हम बातचीत करने के लिये तैयार नहीं हैं । आपको याद होगा कि हमारे डिफेंस मिनिस्टिर ने उनके आर्मी चीफ को इनवाइट किया था कि आप हमारे देश में आइए तो उनके प्रधान मंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि अभी कोई अवसर नहीं है। for building confidence between India and Pakistan इसलिये हमारे आर्मी चीफ का वहां जाने और विजिट करना फूटफुल नहीं होगा, मीनिंगफुल नहीं होगा । क्या हम यह बात नहीं कह सकते कि इस स्थिति में जब तक आप अपनी मानसिकता स्पष्ट नहीं करते, किसी भी बात का कोई फुटफुल रीजल्ट नहीं होगा । अब पाकिस्तान कह रहा है कि जब तक काश्मीर का मसला हल नहीं होगा, हमारे रिलेशंस नार्मल नहीं हो सकते । काश्मीर हमारा है, यह हम नहीं कह रहे हैं । यह बात हमारी तरफ से होनी चाहिये कि जब तक आक्यूपाइड काश्मीर पाकिस्तान नहीं छोड़ता तब तक हमारे रिलेशंस नार्मल नहीं हो सकते । एक बार भी हमने हिम्मत के साथ यह बात नहीं कही । पाकिस्तान आक्यूपाइड काश्मीर लिबरेट करवायेंगे, हमारा यह विषय होना चाहिये । वह हमारा अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप न करे, यह दूसरा विषय होना चाहिये । अफगानिस्तान में अपनी ज्यादा चीजें बढ़ाते हैं, क्योंकि यह माना जा रहा है कि अफगानिस्तान को हमने बिट्रे किया । हमने उनकी मुश्किल में उनकी मदद नहीं की । अफगानिस्तान को भी अपनी सीमा में रहना चाहिये । मुजाहिद्दीन या इनफिलट्रेटर्स को अगर वे इधर भेजते हैं, तो उनसे भी बातचीत का कोई आधार नहीं रह जाता है । हम लोगों को बातचीत नहीं करनी चाहिये । यह मेरा निश्चित मत है । इसलिये बातचीत का आधार और उसके पिछले इतिहास एवं परिणामों को सामने रखकर ही आगे बढ़ें यही मेरा निवेदन है ।

धन्यवाद ।

उपसभापति : सत्य प्रकाश मालवीय जी आप सवाल पूछ लीजिये।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा । माननीय उपसभापति महोदया, सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा था 15 अगस्त, 1947 को बटवारा हुआ । इसके दो हिस्से बने । उसके बाद पाकिस्तान और बंगलादेश बना। पाकिस्तान

का हिस्सा कभी हमारे देश का हिस्सा था। डा. राममनोहर लोहिया ने उस समय कहा था यह एक नकली बंटवारा है लेकिन पाकिस्तान से हमारे रिश्ते न केवल दोस्ती के होने चाहिए बल्कि भाईचारे के होने चाहिएं। इसलिए जो बातचीत की प्रक्रिया है वह बराबर जारी रहनी चाहिए। शिमला समझौता की भी यही मंशा थी। उसके बाद कई बार बातचीत हो चुकी है। बातचीत में मैं कोई हर्ज नहीं समझता। रियाकाफ्रेंस में तय हुआ था कि पाकिस्तान के परराष्ट्र मंत्री भारत आयेंगे और हमारे परराष्ट्र मंत्री से बातचीत करेंगे। 16 अगस्त की तारीख तय हुई थी। मेरे-तीन-चार प्रश्न हैं। कृष्णलाल शर्मा जी निवेदन कर चुके हैं कि नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधान मंत्री हैं, ने 5 अगस्त को एक स्टेटमेंट दिया है "Pakistan had a mission to liberate Kashmir." मैं यह सुझाव देना चाहता हूं जो बातचीत हो उसमें भारत की ओर से जो विदेश सचिव है वह सख्ती से इस बात को रखे कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और जो वह कहते हैं "Pakistan had a mission to liberate Kashmir."

इसको" बारे में भारत की जनता में और भारत सरकार में बहुत रोष है, गुस्सा है। इस तरह के उत्तेजनात्मक वक्तव्य पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को नहीं देने चाहिए। दूसरे भारत सरकार बराबर इस बात को कहती है कि आतंकवाद बढ़ रहा है कश्मीर में, पंजाब में या उत्तर प्रदेश के तराई के हिस्से में। अभी हाल में अहमदाबाद में काफी मात्रा में आर्म्स बरामद हुए हैं। जैकब साहब ने अपनी स्टेटमेंट में भी बताया है कि जो खबरें मिली हैं उनसे पता चलता है कि आर्म्स पाकिस्तान की ओर से सप्लाई हो रहे हैं। यह चीज तूल में रहनी चाहिए। हमारे देश की एकता में खतरा वे पहुंचा रहे हैं यहां पर आतंकवाद को बढ़ावा दे कर जो आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं इसको भारत सरकार और भारत के लोग बर्दाशत नहीं करेंगे। मंत्री जी जब आप उत्तर दीजियेगा तो कम से कम इन सारी बातों को जिक्र करियेगा कि 16 अगस्त से 19 अगस्त तक जो विदेश सचिव स्तर की बातचीत होने वाली है उनमें इसको रखा जा रहा है या नहीं ?

SHRI JAGMOHAN (Nominated): Thank you, Madam, I have four short clarifications or points to make.

The first is that when any Secretaries-level or other discussions take place between India and Pakistan, Pakistan uses this as an opportunity to intensify its activity in Kashmir. Now, for example, a statement was made by the Prime Minister of Pakistan, Mr. Nawaz Sharif: कश्मीर बनेगा पाकिस्तान That gives a lot of encouragement to the people in Kashmir to indulge in subversive activities again. Likewise, whenever there is a discussion at the Secretaries-level, the Kashmiris always observe a *bandh*: They say that the local people are not being represented. Thus, both ways anti-Indian sentiments are whipped up on the occasion. This point needs to be taken care of by the Central Government.

The second point is that in the contemporary world everything happens by remote control. You know, this is a time of electronics. What Pakistan is really doing is it is indulging in murders by a remote control. It is supplying arms and lethal weapons and innocent people are being killed. In Punjab, now the police officials and their relatives are being killed, I don't think that only the man who actually kills is the murderer. Those who are abetters, they are also equally guilty. How do you sit at the same table with virtual murderers? Due to some compulsion, it may be necessary to talk. Due to other factors which are equally relevant it may necessary to talk. We should make our point very strongly and very clear that Pakistan is actually indulging in mass furders and also using Kashmiris as a cannon fodder. This is the second point which needs to be taken care of.

The third point—which I raised during the Question Hour also and to which

a proper reply was not forthcoming—relates to Direct Dialling Facilities to PoK. There are two points in it; one is legal and the other is practical. If there is an agreement between India and Pakistan about the extension of Direct Dialling Facilities, how have you extended this facility to PoK which India does not recognise as part of Pakistan? How is the Direct Dialling Facility available between Srinagar and Muzaffarabad? And, this Direct Dialling Facility is giving a sort of facility to the terrorists who indulge in talking and settling things, issuing orders, taking commands, etc. By various other methods, they go on giving messages which can be given in a short time and they cannot be even detected for various reasons which I do not want to go into here.

The fourth point which I would like to make is that a very nefarious type of propaganda is being carried on by Pakistan in foreign countries. They are making use of all types of declarations and court things which are being done in Kashmir and the Indian Government is not taking effective measures. For example, some writ petitions were filed in Courts in which all types of things were said against India and then, those very writ petitions were reproduced and distributed in America. This is what the ex-Chief Justice of such and such High Court said in the Jammu and Kashmir High Court. But there is no counter to present the fact that the writ petitions were dismissed as false. I did not see it in the United States. But hundreds of pamphlets were being distributed on the basis of those writ petitions. This is what the ex-Chief Justice has sworn in an affidavit. A simple reply could have been given by our people saying that this is all false, this is a technique of propaganda and the writ petitions had actually been dismissed by the Courts of India. And, why don't you prosecute those who indulge in these things like sedition? They are living here in India. Why don't you do that? Once you start prosecution, you can easily and effectively give an answer in the propaganda arena in America that such people are indulging in sedition, that the are facing the consequences of law and that they are making this propaganda to save themselves from the consequences of law.

These are the four points which I would request the Minister to kindly consider.

SHRI JOHN. F. FERNANDES (Goa): Madam, whenever we read in newspapers that there are going to be talks at Prime Ministers' level or Foreign Ministers' level or Secretaries' level with Pakistan, we find that it is India which takes the initiatives, be it Rio de Janeiro or Davos or Colombo or Kathmandu. That shows the seriousness of the Government of India to settle issues through negotiation and dialogue. The very fact that the Simla Agreement was signed in India proves my argument. Madam, whenever there are terrorist activities, we have raised the issue in many international forums. As there is no cold-war now, you can name the so-called foreign power, Pakistan, and say, "You are perpetuating terrorism in India." But behind the scene, we see that some other powers are at war with India by proxy because whenever arms are seized, which are supplied to the terrorists in India by Pakistan, we find that they are never made in Pakistan. This AK-47 or AK-53 is not made in Pakistan, but in some other countries. These countries pay lip-sympathy to India because of terrorist attacks by Pakistan on India through proxy. I want the hon. Minister to take note of this and to react to thi point.

As the hon. Member, Mr. Jagmohan rightly mentioned, whenever we hear that talks are to be held, the pressure on terrorists in India is increased. And, this is proved when we see the bashing of diplomats, Indian diplomats. There are already diplomatic codes. I think there is the General Agreement on diplomatic missions. But I am happy that the Minister has said that he is going to have more agreements with Pakistan to protect the interests of diplomatic missions. This is to be welcomed. It was shocking again that Pakistan

tried to impose an aids embargo on Indian Nationals. That was most shocking. This is how they tried to stall all the attempts made by the Government of India towards a peaceful negotiation. It is said off and on that Pakistan wants to settle scores with India for abetting and helping the freedom fighters in Bangladesh in 1971. Madam, we may recall that 80 lakh refugees from Bangladesh were dumped on India and it was only through legal means, through the sanctions of the United Nations and with the consent of all the Super Powers, that we marched into Bangladesh to liberate the people of that country. I don't think it is justified for Pakistan to fight a war through proxy with India and kill the innocent civilians. It is a most inhuman and a cowardly act. Whenever there is any terrorist activity in our country, the hon. Home Minister comes and makes a statement and our finger is pointed at Pakistan and we always condemn this act. But nothing is done at the international fora to bring pressure on Pakistan. It was very rightly mentioned by one of my friends from the Opposition about starting a hotline. After a meeting of the SAARC fora, the former Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi, had started a hotline between Islamabad and New Delhi. I do not know whether this hotline is functioning because two new Governments and two new Prime Ministers held office after him. I do not know whether that relation was maintained or not. I would like to know whether that hotline is still functioning. I want the Minister to react to this point.

We see that there is a Pressler amendment in America according to which America will not supply arms to Pakistan. But it is argued that the Pressler amendment will only apply to the Government arms. We see that most of the American arms manufactured by private firms are supplied to Pakistan and these arms are not used against anyone but India. I would request the hon. Minister of State for External Affairs to see that more and more pressure is brought though the so-called Super Powers on Pakistan so that Pakistan agrees to come to the negotiating table. Thank you.

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मौम अफजल (उत्तर प्रदेश) : मैडम जो बातचीत हो रही है, इस सिलसिले में मैं समझता हूं कि बात चीत तो होनी ही चाहिये। कई शेर यहां सुनाये गये, इस मौके पर मुझे भी एक शेर याद आ गया।

"दुश्मनी जमकर करो लेकिन यह गुंजाइश रहे,

कल अगर फिर दोस्त हो शर्मिंदये खातिर न हो।"

यह तो हिन्दुस्तान का शुरु से ही रवैया रहा है पाकिस्तान के साथ। मैं कुछ अर्सा पहले ईरान गया था जब वहां जंग हो रही थी। ईरान की तमाम सड़कों के ऊपर एक ही नारा सुनाई देता था कि "जंग जंग तासी रूबी", आखिरी लम्हें तक जब तक देश को आजाद नहीं कर लेते जंग जारी रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही नारा ईराक में भी सुनने को मिलता था। लेकिन आठ साल के बाद हमने देखा कि दोनों मुल्क तबाही के मुहाने पर पहुंच गये और उसके बाद उनको सेटलमेंट करना पड़ा, जंग रोकनी पड़ी और वह सेटलमेंट उनको मेज पर बैठकर करना पड़ा। इसलिय जो इस कि म के सजेंशस आते हैं कि पाकिस्तान से डटकर मुकाबला करो तो ऐसे जो सशंस आते हैं उनको मैं अहमियत नहीं देता। यह अलावा भड़काने और साम्राज्यवादी हुमतों के इशारे पर काम करने के सिवाय दूसरा काम नहीं करते। अफसोस की बात है कि जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के दरम्यान इन तमाम रिलेशंस को लेकर गुफ्तगू होती है तो हम उस पहलू को नजरअंदाज कर देते हैं और कठपुतलियां हमें चलाती रहती हैं। लेकिन तार कहां जुड़ा हुआ है उसको हम नजरदांज कर देते हैं अभी हमारे कृष्ण लाल शर्माजी ने अफगानिस्तान का मामला उठाया। बिला सुभहा, उनकी बात बहुत सही थी। लेकिन अफगानि तान में पाकिस्तान को मदाखलत किस के इशारे पर थी, अमेरिका

के इशारे पर। आज वहां अमेरिका का इंटरेस्ट खत्म हो गया है। आज अफगानिस्तान का हाल सब के सामने है, सारी दुनिया देख रही है।

मोहतरमा, आप बातचीत करने जा रहे हैं। मैं इस सिलसिले में एक-दो चीजें कहना चाहता हूं। काश्मीर हिन्दुस्तान का अटूट अंग है।

इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। मैं तो इससे भी आगे बढ़ कर के कहता हूं कि काश्मीर में अक्सरियत मुसलमानों की है और मुसलमान हिन्दुस्तान के दूसरे इलाकों में भी बसते हैं और छोटी-मोटी तादाद नहीं है 20 करोड़ मुसलमान बसते हैं। तो कश्मीर न सिर्फ हिन्दुस्तान का एक अटूट अंग है, बल्कि कश्मीरी मुसलमान हिन्दुस्तानी का अटूट अंग है। आपको पूछना चाहिये पाकिस्तान से यह बात कि वहां पर जो इस्लाम के नाम पर तहरीक चलाई जा रही है जैसे अफगानिस्तान में चलाई गई जो इस्लाम के हवाले से कश्मीरी मुसलमान को आजादी दिलाने की बात होती है, तो पूछना चाहिये कि हिन्दुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान क्या मुसलमान हैं या नहीं। क्या आप उनके एक हाथ को काट कर के उनको अपाहिज बना कर इस्लाम की कोई खिदमत कर रहे हैं। मुझे अफसोस है कि जगमोहन जी ने सही त्वज्जो दिलाई। मोहतरमा, मैंने 19–20 मुमालिक के दौरे किये हैं। मैं बड़े वसूक के साथ यह बात कह सकता हूं कि पाकिस्तान दूसरे मुमालिक के अन्दर जो प्रोपेगंडा कर रहा है उसका कोई तोड़ हमारे इम्बेसीज वहां नहीं कर पाई है। यह बहुत अफसोसजनक बात है। लन्दन जा कर देखिए, वहां के जो अखबारात हैं, वह पाकिस्तानी मोअक्कफ शाए करते हैं। सऊदी अरब और दूसरे अरब मुमालिक में मैं गया हूं। मैंने देखा आज से करीब तीन चार साल पहले फ्रंट पेज पर हिन्दुस्तान के एक दो न्यूज छपा करते थे, लेकिन आज अखबारों में अचानक हिन्दुस्तानी मौअक्कफ नजर ही नहीं आता है। फ्रंट पेज पर न्यूज पाकिस्तानी मौअक्कफ की हिमायत होती है। यह तबदीली कैसे आई। आपके सिफारतखाने वहां क्या कर रहे हैं। (लंदन में हाई कमिश्नर से मैंने बात की। मैंने यह बताया कि यहां पर उर्दू के अखबारात एक तीसरी फोर्स है। उनके जरिए पाकिस्तान एक जबरदस्त प्रोपेगंडा हमारे खिलाफ लांच किए हुए है। वहां जो एशियन बसते हैं खास तौर पर जो मुसलमान हैं उनके अन्दर उसका पूरा होल्ड है क्योंकि उन्होंने पूरे उर्दू प्रेस को कंट्रोल किया हुआ है। मैंने पूछा कि आपने इसके जबाव में क्या किया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे एम्बेजडर साहब ने इस बात का एतराफ किया कि हमारी कारकर्दगी में कुछ कमी है। तो एक ओवर-आल माहौल बनता है। जाहिर है जब हम बातचीत करते हैं, कृष्ण लाल शर्मा जी ने बड़ी सही बात कही कि हमको लगता है कि हम खुशामद में लगे हुए हैं। हमें खुशामद नहीं करनी चाहिए, ओवर-आल इम्पेक्ट बढ़ाना चाहिए, पूरी दुनियां को अपने मौअक्कफ को जाहिर करना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं। इराक हमारा एक ऐसा दोस्त था जिसने कश्मीर के मसले पर हमारे मौअक्कफ की हिमायत की लेकिन जब इराक पर नाकाबंदी की गई अमरीका की तरफ से तो हमने शर्मनाक हद तक खामोशी अखितयार की और उसकी कोई मदद नहीं की जिसका नतीजा यह हुआ कि आज हम उस सपोर्ट से भी महरूम हो गये हैं। तो डोर कहां से हिल रही है; इस पर भी तवज्जो रहनी चाहिए। इससे हट कर के मैं एक बात कहूंगा; पाकिस्तान बना यह बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। 1947 में पाकिस्तान बना। उसके बाद कुछ लोग वहां चले गये और कुछ यहां पर रह गये। अज़ीज़ो अकारिब, रिश्तेदारियां आज भी बरकरार हैं।

पाकिस्तान के अन्दर सिर्फ मैं उन लोगों की बात नहीं करता जिनकी रिश्तेदारी यहां पर है वह लोग जिनकी कोई रिश्तेदारी हिन्दुस्तान में नहीं है वह हिन्दुस्तान आने के लिए, देखने के लिए तड़पते हैं। लोगों के रिश्ते इतने मजबूत हैं। मैं आपको बहुत सारी ऐसी मिसालें दे सकता हूं। वहां रहने वाला कोई मुसलमान है और यहां रहने वाला हिन्दू है, कोई रिश्तेदारी नहीं है लेकिन उनके आपस के रिलेशन ऐसे हैं कि भाइयों से भी ज्यादा हैं। सियासत कहीं और ले जाती है और आवामी रुझान कहीं और ले जाता है। आज भी मैं समझता हूं कि इस पर मुझे बड़ी खुशी है कि आवामी रुझान हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के अन्दर आज भी दोस्ती वाला है। दोनों मुल्कों के लोग आज भी चाहते हैं कि दोस्ती के रिश्ते ज्यादा से ज्यादा मजबूत हों। लेकिन सियासत हमें इसकी इजाजत नहीं देती है। मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं (**समय की घंटी**) सैकड़ों लोग अपनी अजीजों अकारिब से मिलने के लिए पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान से बहुत सारे लोग यहां आते हैं। सिंध से आते हैं, इस्लामाबाद से आते हैं, लाहौर से आते हैं और कराची से भी आते हैं और इसी तरह से यहां से भी जाते हैं। लेकिन अभी हाल ही में तीन महीने पहले पाकिस्तान सरकार ने अपनी वीजा की पालिसी जो लिबरल थी उसको खामख्वाह बेहद सख्त कर दिया है जिसका नतीजा यह है कि आज पाकिस्तान इम्बेसी में भीड़ लगी रहती है। हमने वहां के अफसरान से बात की कि मसला क्या है। आखिर हमारी इम्बैसी हिंदुस्तान की वहां पर है। वह भी तो एक लिबरल पालिसी के तहत पाकिस्तानियों को वीजा देती है। आज आप देख लीजिए ट्रेन भर करके पाकिस्तान से आती है लेकिन हिंदुस्तान से जो लोग जाने वाले हैं उन पर पाबंदी लगा दी गयी है। क्यों, किस वजह से यह है? जो पालिसी वीजा की उनकी है वही पालिसी हमारी है। जो हमारी है वही उनकी भी होनी चाहिए। लेकिन अचानक यह तब्दीली कैसे आ गयी। मैं तो मैडम, यहां तक कहूंगा, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि रोजाना सुबह को–बहुत सारे मेम्बरान पार्लियामेंट यहां जानते हैं इस बात को कि रोजाना सुबह को 2–4–5 लोग आ जाते हैं कि पाकिस्तान का वीजा दिलवा दीजिए। मैंने तो एक दिन मजाक में कहा कि भाई मैं यहां एक बोर्ड लगा देता हूं अपने घर पर कि पाकिस्तान का वीजा इस मकान में नहीं मिलता है बल्कि पाकिस्तान की इम्बैसी में मिलता है। अब क्या करें, लोग परेशान है। वहां उन्होंने वीजा के लिए सख्ती की हुई है (**समय की घंटी**) कहा यह जाता है कि वहां से आदेश है, इस्लामाबाद से कि आप आने वालों को डिसकरेज करें और जो लोग उनकी बाकायदा हम इंक्वायरी करें। अच्छा चलिए, आप इंक्वायरी कर लीजिए। लेकिन किसी को इमरजेंसी में जाना है। ऐसे ऐसे रिश्ते हैं। किसी का बाप वहां पर है, किसी की मां वहां पर है, किसी का सगा भाई वहां पर है, अगर कोई डेथ बैड पर पड़ा हुआ है, कोई इमरजेंसी है तो वे तय कैसे करेंगे कि इस आदमी को इमरजेंसी है या नहीं है। अब अपको टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है। एक टेलीफोन आ जाता है कि तुम्हारा कोई आदमी बीमार है, आपको आना है तो आ जाइये, देख लीजिए उसको, और जब वह वीजा लेने जाता है तो वे कहेंगे कि हम तीन महीने के बाद आपको जवाब देंगे कि आप इस काबिल हैं भी कि पाकिस्तान जा सकें या नहीं जा सकें। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस मसले को आप एजेंडा में शामिल करें। अगर पाकिस्तान अपनी पालिसी को लिबरल नहीं करता तो फिर मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी उसी तरह का बर्ताव करें।

दूसरा, मैं काफी दिन से एक बात कहना चाह रहा हूं। इस सिलसिले में मैंने एक चिट्ठी भी लिखी कि लाहौर का जो कस्टम का चेक पोस्ट है वहां एक लूट मची हुई है। मैडम, यहां, से जो लाहौर, पाकिस्तान लोग जाते हैं वे अमूमन–जो आसूदा हाल हैं जो अच्छे खाते पीते लोग हैं वे तो हवाई जहाज से चले जाते हैं लेकिन जो बिल्कुल गरीब तबका है वह रेल से सफर करता है . . .

उपसभापति : संक्षेप में।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : एक मिनट में मैं खत्म कर रहा हूं। लाहौर के अंदर मुसाफिरों की बुरी तरह से लूट मची हुई है। एक पासपोर्ट–में इमिग्रेशन वाले इन्दराज करने के लिए पर पासपोर्ट एक सौ रुपए चार्ज करते हैं। उसके बाद कस्टम वाले, जबकि पाकिस्तान में कस्टम खत्म हो चुका है, कस्टम वाले कपड़े छोड़कर बाकी सब छीन लेते हैं। यह भी आपको जरूर टेक अप करना चाहिए। यह गरीब लोगों की लूटमार का सिलसिला जो लाहौर के रेलवे स्टेशन और चेक पोस्ट पर मचाया हुआ है यह आखिर कब खत्म होगा।

दूसरा, अटारी बार्डर को भी चेक करें। वजीरे दाखिला नहीं है। वहां से जो सुन सुन कर लोग आते हैं तो हमारी तरफ के लोग भी भड़कते हैं . . .

उपसभापति : वजीरे दाखिला हैं।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : कि लूटमार उधर हो रही है तो थोड़ी इधर भी कर लें।

उपसभापति : वजीरे दाखिला हैं। पीछे बैठ हुए हैं।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है।

उपसभापति : खारिजा भी हैं, दाखिला भी है। अब आप बैठ जाइये।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : मैडम, मैं आखिर में यही कहूंगा कि जो बातचीत हो रही है वह बहरहाल जारी रखनी चाहिए। काश्मीर का ही एक मसला है। लेकिन अवाम के अंदर बड़ा रुझान है और अच्छा रुझान है दोनों मुल्कों में। कुछ इसके अंदर हम लोगों को जो आदान प्रदान है वह बढ़ाना चाहिए, बीच में कल्चरल रिलेशंस को बनाने के लिए काफी काम हुआ था। उसमें काफी काम किया गया था। लोग आने लगे थे, जाने लगे थे। इससे भी रिश्ते मजबूत हो सकते हैं और कुछ प्रेशर भी बढ़ाया जा सकता है इससे। अपने मुल्क के अंदर भी वहां से लोग आते हैं। वहां भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो यह गलमझते हैं कि काश्मीर में जो मदाखलत है पाकिस्तान की वह बिल्कुल गलत है। वहां ऐसे बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। हमको यह देखना चाहिए और अपना केस उनके सामने रखना चाहिए और खास तौर से मैं कहूंगा कि आपको यह बात जरूर रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, इस्लाम के नाम पर काश्मीर को आजाद कराना चाहते हैं–अगर वे वैसे ही आजाद कराना चाहते हैं तो मैं एक मिनट को समझ सकता हूं कि उनकी बड़ी हमदर्दी है लेकिन इस्लाम के नाम पर अगर वे कराना चाहते हैं तो हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं इसलिए कि काश्मीरी मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमानों का भी एक अटूट अंग हैं और अगर पाकिस्तानी इस अटूट अंग को तोड़ना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि वे हिंदुस्तान के मुसलमान को बेकार, लूला और लंगड़ा बनाना चाहते हैं। इसको हिंदुस्तान का मुसलमान कभी बर्दाश्तनहीं करेगा।

بات ہے کہ جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ان تمام ریشنس کو لیکر گفتگو ہوتی ہے تو ہم اس پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ابھی ہمارے کرشن لعل شرما جی نے افغانستان کا مسئلہ اٹھایا۔ بلاشبہ ان کی بات صحیح تھی لیکن افغانستان میں پاکستان کی مداخلت کس کے اشارہ پر تھی۔ امریکہ کے اشارہ پر۔ آج وہاں امریکہ کا انٹرسٹ ختم ہوگیا ہے۔ آج افغانستان کا حال سب کے سامنے ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔

محترمہ۔ آپ بات چیت کرنے کو جا رہے ہیں۔ میں اس سلسلے میں ایک دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں۔ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں کہ کشمیر میں اکثریت مسلمانوں کی ہے اور مسلمان ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں بھی بستے ہیں اور چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہے ۲۰ کروڑ مسلمان بستے ہیں۔ تو کشمیر نہ صرف ہندوستان کا ایک اٹوٹ انگ ہے بلکہ کشمیری مسلمان ہندوستان کے مسلمانوں کا اٹوٹ انگ ہے۔ آپ کو پوچھنا چاہیے پاکستان سے یہ بات کہ وہاں پر جو اسلام کے نام پر تحریک چلائی جا رہی ہے۔ جیسے افغانستان میں چلائی گئی جو اسلام کے حوالے سے کشمیری مسلمانوں کو آزادی دلانے کی بات ہوتی

شری محمد افضل (اتر پردیش): میڈم۔ جو بات چیت ہو رہی ہے اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت تو ہونی ہی چاہیے۔ کئی شعر یہاں سنائے گئے اس موقع پر مجھے بھی ایک شعر یاد آگیا...

"دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے
کل اگر پھر دوست ہوں شرمندہ خاطر نہ ہوں"

یہ تو ہندوستان کا شروع سے ہی رویہ رہا ہے پاکستان کے ساتھ۔ میں کچھ عرصہ پہلے ایران گیا تھا جب وہاں جنگ ہو رہی تھی۔ ایران کی تمام سڑکوں کے اوپر ایک ہی نعرہ سنائی دیتا تھا کہ "جنگ جنگ تا سی روبی" آخری لمحہ تک جب تک دیش کو آزاد نہیں کر لیتے جنگ جاری رہے گی۔ بالکل ایسا ہی نعرہ عراق میں بھی سننے کو ملتا تھا لیکن آٹھ سال کے بعد ہم نے دیکھا کہ دونوں ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے اور اس کے بعد انکو سٹلمنٹ کرنا پڑا جنگ روکنی پڑی اور وہ سیٹلمنٹ انکو میز پر بیٹھ کر کرنا پڑا۔ اس لیے جو اس قسم کے سجیشنس آتے ہیں کہ پاکستان سے ڈٹ کر مقابلہ کرو ایسے جو سجیشنس آتے ہیں تو ان کو میں اہمیت نہیں دیتا۔ یہ علاوہ بھڑکانے اور سامراجیہ وادی حکومتوں کے اشارہ پر کام کرنے کے سوائے دوسرا کام نہیں کرتے۔ افسوس کی

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

انہوں نے پورے اردو پریس کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے اس کے جواب میں کیا کیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایمبیسڈر صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہماری کارکردگی میں کچھ کمی ہے۔ تو ایک اوور آل ماحول بنتا ہے۔ ظاہر ہے جب ہم بات چیت کرتے ہیں کرشن لال شرما جی نے بڑی صحیح بات کہی کہ ہم کو لگتا ہے کہ خوشامد میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں خوشامد نہیں کرنی چاہیے۔ اوور آل اسپیکٹ بڑھانا چاہیے۔ پوری دنیا کو اپنے مؤقف کو ظاہر کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عراق ہمارا ایک ایسا دوست تھا جس نے کشمیر کے مسئلے پر ہمارے مؤقف کی حمایت کی لیکن جب عراق پر ناکہ بندی کی گئی امریکہ کی طرف سے تو ہم نے شرمناک حد تک خاموشی اختیار کی اور اس کی کوئی مدد نہیں کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج اس سپورٹ سے بھی محروم ہو گئے ہیں تو ڈور کہاں سے ہل رہی ہے۔ اس پر بھی توجہ رہنی چاہیے اس سے ہٹ کر کے میں ایک بات کہوں گا پاکستان بنا بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ ۱۹۴۷ میں پاکستان بنا۔ اس کے بعد کچھ لوگ وہاں چلے گئے اور کچھ یہاں پر رہ گئے۔ عزیز و اقارب رشتہ داریاں آج بھی برقرار ہیں۔ پاکستان کے اندر صرف

تو پوچھنا چاہیے کہ ہندوستان کے ۱۰ کروڑ مسلمان کیا مسلمان ہیں یا نہیں۔ کیا آپ ان کے ایک ہاتھ کو کاٹ کر ان کو اپاہج بنا کر اسلام کی کوئی خدمت کر رہے ہیں مجھے افسوس ہے اور جگموہن جی نے صحیح توجہ دلائی۔ محترم میں نے ۲۰-۱۹ ممالک کے دورے کئے ہیں۔ میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان دوسرے ممالک کے اندر جو پروپیگنڈہ کر رہا ہے اس کا کوئی توڑ ہماری ایمبیسیز وہاں نہیں کر پائی ہیں۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ لندن جا کر دیکھئے۔ وہاں کے جو اخبارات ہیں وہ پاکستانی موقف شائع کرتے ہیں۔ سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک میں میں گیا ہوں۔ میں نے دیکھا آج سے قریب تین چار سال پہلے روزانہ فرنٹ پیج پر ہندوستان کے ایک دو نیوز چھپا کرتے تھے۔ لیکن آج اخباروں میں اچانک ہندوستانی مؤقف نظر ہی نہیں آتا ہے۔ فرنٹ پیج پر نیوز پاکستانی مؤقف کی حمایت میں ہوتی ہے۔ یہ تبدیلی کیسے آئی۔ آپ کے سفارت خانے وہاں کیا کر رہے ہیں لندن میں ہائی کمشنر سے میں نے بات کی۔ میں نے یہ بتایا کہ یہاں پر اردو کے اخبارات ایک تیسری فورس ہیں۔ وہاں جو ایشین بستے ہیں۔ خاص طور پر جو مسلمان ہیں انکے اندر اس کا پورا ہولڈ ہے کیونکہ

پاکستان سرکار نے اپنی ویزا کی پالیسی جو لبرل تھی اس کو خواہ مخواہ بے حد سخت کر دیا گیا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان ایمبیسی میں بھیڑ لگی رہتی ہے۔ ہم نے وہاں کے افسران سے بات کی کہ مسئلہ کیا ہے۔ آخر ہماری ایمبیسی ہندوستان کی وہاں پر ہے۔ وہ بھی تو وہاں پر ہے۔ وہ بھی تو ایک لبرل پالیسی کے تحت پاکستانیوں کو ویزا دیتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے ٹرین بھر کر کے پاکستان سے آئی ہے۔ لیکن ہندوستان سے جو لوگ جانے والے ہیں۔ ان پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ کیوں کس وجہ سے یہ ہے۔ جو پالیسی ویزا ان کی ہے وہی پالیسی ہماری ہے۔ جو ہماری ہے وہ ہی ان کی بھی ہونی چاہیے۔ لیکن اچانک یہ تبدیلی کیسے آ گئی۔ میں تو سمجھتا ہوں یہاں تک کہوں گا کہ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ روزانہ صبح کو۔ بہت سارے ممبران پارلیمنٹ یہاں جانتے ہیں اس بات کو روزانہ صبح کو دو چار یا پانچ لوگ آجاتے ہیں کہ پاکستان کا ویزا دلوا دیجئے۔ میں نے تو ایک دن مذاق میں کہا کہ بھائی میں یہاں ایک بورڈ لگا دیتا ہوں اپنے گھر پر کہ پاکستان کا ویزا اس مکان میں نہیں ملتا ہے بلکہ پاکستان ایمبیسی میں ملتا ہے۔ اب کیا کریں لوگ پریشان ہیں۔ وہاں انہوں نے ویزا کیلئے سختی کی ہوئی ہے۔ ..."وقت کی گھنٹی"... کہا یہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جن کی رشتہ داریاں یہاں پر ہیں۔ وہ لوگ جن کی کوئی رشتہ داری ہندوستان میں نہیں ہے۔ وہ ہندوستان آنے کے لیے۔ دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں۔ لوگوں کے رشتے اتنے مضبوط ہیں۔ میں آپ کو بہت ساری ایسی مثالیں دے سکتا ہوں۔ وہاں رہنے والا کوئی مسلمان ہے اور یہاں رہنے والا ہندو ہے۔ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ لیکن ان کے آپس کے ریلیشن ایسے ہیں کہ بھائیوں سے بھی زیادہ۔ سیاست کہیں اور لے جاتی ہے۔ اور عوامی رجحان کہیں اور لے جاتا ہے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پر مجھے بڑی خوشی ہے کہ عوامی رجحان ہندوستان اور پاکستان کے اندر آج بھی دوستی والا ہے۔ دونوں ملکوں کے لوگ آج بھی چاہتے ہیں کہ دوستی کے رشتہ زیادہ مضبوط ہوں۔ لیکن سیاست ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ میں تو یہ دلانا چاہتا ہوں... "وقت کی گھنٹی"... سینکڑوں لوگ اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے پاکستان جاتے ہیں اور پاکستان سے بہت سارے لوگ یہاں آتے ہیں۔ سندھ سے آتے ہیں۔ اسلام آباد سے آتے ہیں۔ لاہور سے آتے ہیں اور کراچی سے بھی آتے ہیں اور اسی طرح سے یہاں سے بھی جاتے ہیں۔ لیکن ابھی حال ہی میں تین مہینے پہلے

میڈم، یہاں سے جو لاہور۔ پاکستان لوگ جاتے ہیں وہ عموماً جو آسودہ حال ہیں جو اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ ہوائی جہاز سے چلے جاتے ہیں لیکن جو بالکل غریب طبقہ ہے وہ ریل سے سفر کرتا ہے...

اُپ سبھاپتی: سنکشیپ میں۔

شری محمد افضل عرف م۔ افضل: ایک منٹ میں میں ختم کر رہا ہوں۔ لاہور کے اندر مسافروں کی بری طرح لوٹ مچی ہوئی ہے۔ ایک پاسپورٹ میں امیگریشن والے اندراج کرنے کے لیے پر پاسپورٹ ایک سو روپے چارج کرتے ہیں۔ اس کے بعد کسٹم والے جبکہ پاکستان میں کسٹم ختم ہو چکا ہے۔ کسٹم والے کپڑے چھوڑ کر باقی سب چھین لیتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ یہ غریب لوگوں کی لوٹ مار کا سلسلہ جو لاہور کے ریلوے اسٹیشن اور چیک پوسٹ پر مچا ہوا ہے۔ یہ آخر کب ختم ہوگا۔

دوسرا اٹاری بارڈر کو بھی چیک کریں وزیر داخلہ نہیں ہیں وہاں سے جو سن سن کر لوگ آتے ہیں۔ تو ہماری طرف کے لوگ بھی بھڑکتے ہیں...

اپ سبھاپتی: وزیر داخلہ ہیں۔

شری محمد افضل عرف م۔ افضل: کہ لوٹ مار ادھر ہو رہی ہے تو تھوڑی ادھر بھی کریں۔

اپ سبھاپتی: وزیر داخلہ ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔

جاتا ہے کہ وہاں سے آدیش ہے اسلام آباد سے کہ آپ آنے والوں کو ڈسکرج کریں اور جو لوگ آئیں ان کی باقاعدہ ہم انکوائری کریں اچھا چلیے۔ آپ انکوائری کو لیجئے۔ لیکن کسی کو ایمرجنسی میں جانا ہے۔ ایسے ایسے رشتے ہیں۔ کسی کا باپ وہاں پر ہے۔ کسی کی ماں وہاں پر ہے۔ کسی کا سگا بھائی وہاں پر ہے۔ اگر کوئی ڈیتھ بیڈ پر پڑا ہوا ہے۔ کوئی ایمرجنسی ہے۔ تو وہ طے کیسے کریں گے کہ اس آدمی کو ایمرجنسی ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ کو ٹیلیفون کی سوید ھا اپلبدھ ہے۔ ایک ٹیلیفون آجاتا ہے۔ کہ تمہارا کوئی آدمی بیمار ہے۔ آپ کو آنا ہے تو آجائیے دیکھ لیجئے اس کو۔ اور جب وہ ویزا لینے جاتا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم تین مہینے کے بعد آپ کو جواب دینگے۔ کہ آپ اس قابل ہیں کہ بھی نہیں کہ پاکستان جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس مسئلے کو آپ ہمدردانہ غور کریں [illegible] کہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں کرنا تو پھر میں [illegible] کروں گا کہ آپ بھی اسی طرح کا [illegible]

دوسرا میں کافی دن سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس سلسلہ میں میں نے ایک چٹھی بھی لکھی ہے کہ لاہور کا جو کسٹم کا چیک پوسٹ ہے۔ وہاں ایک لوٹ مچی ہوئی ہے۔

یہ دیکھنا چاہیے اور اپنا کیس انکے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور خاص طور سے میں کہوں گا کہ آپ کو یہ بات ضرور رکھنی چاہیے۔ کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں۔ اسلام کے نام پر کشمیر کو آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ ویسے ہی آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ تو میں ایک منٹ کو سمجھ سکتا ہوں کہ ان کی بڑی ہمدردی ہے لیکن اسلام کے نام پر اگر وہ کرانا چاہتے ہیں تو ہم اسکو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اس لیے کہ کشمیری مسلمان ہندوستانی مسلمانوں کا بھی ایک اٹوٹ انگ ہیں۔ اور اگر پاکستانی اس اٹوٹ انگ کو توڑنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بیکار اور لنگڑا بنانا چاہتے ہیں۔ اس کو ہندوستان کا مسلمان کبھی برداشت نہیں کرے گا۔

شری محمد افضل غرف م۔ افضل: میڈم۔ میں آخر میں یہی کہوں گا کہ جو بات چیت ہو رہی ہے۔ وہ بہرحال جاری رہنی چاہیے۔ کشمیر کا ہی ایک مسئلہ ہے۔ لیکن عوام کے اندر بڑا زخمان ہے۔ اور اچھا زخمان ہے۔ دونوں ملکوں میں۔ کچھ اسکے اندر ہم لوگوں کا جو آدان پردان ہے۔ وہ بڑھانا چاہیئے۔ بیچ میں کلچرل ریلیشنس کو بنانے کے لیے کافی کام ہوا تھا۔ اس میں کافی کام کیا گیا تھا۔ لوگ آنے لگے تھے جانے لگے۔ اس سے بھی رشتے مضبوط ہو سکتے ہیں۔ اور کچھ پریشر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے۔ اپنے ملک کے اندر بھی وہاں سے لوگ آتے ہیں۔ وہاں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں جو مداخلت ہے پاکستان کی وہ بالکل غلط ہے۔ وہاں ایسے بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں ہم کو

उपसभापति : सत्या बहिन, कुछ भोजना है । अभी तो काफी हो गया ।

श्रीमती सत्या बहिन :(उत्तर प्रदेश): बिलकुल . . (व्यवधान)

उपसभापति : अच्छा, संक्षेप में एक सवाल पूछ लीजिये ।

श्रीमती सत्या बहिन : बिलकुल संक्षेप में मैं कुछ बिंदुओं की तरफ सदन का और माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि जब से देश का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान जब से अलग-अलग हुये, तब से दोनों देशों के बीच में कटुता बढ़ाने का काम पाकिस्तान खास तौर से करता रहा है ।

मैं तो यह कहूंगी कि यह सच है कि वहां जन समस्याओं से और अपने आपको असफल होने की हताशा में, उन्होंने हमेशा हिन्दुस्तान के खिलाफ कुछ न कुछ दुष्प्रचार किया। कभी सीमा पर तनाव पैदा कर दिया, कहीं कुछ कर दिया (इस तरह से कि लोगों का ध्यान बटे ।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि विदेश सचिवों की वार्ता हो, चाहे विदेश मंत्रियों की हो, चाहे

प्रधान मंत्रियों की हो, पहले बात तो उदको स्पष्ट रूप से यह कह देनी चाहिए कि शिमला समझौता, जो स्व० इंदिरा जी के और स्व० जुल्फिकार भुट्टो को बीच हुआ था, उस समझौते के प्रति पाकिस्तान को कितनी प्रतिबद्धता है कितनी आस्था है ? अगर कहीं सद्भावना का वातावरण बन सकता है, तो शिमला समझौते के तहत ही बन सकता है । अगर आज वह कहें कि भुट्टो जी नही रहे या इंदिरा जी नहीं हैं, तो वह सोचें कि उस समझौते को ही हम बेकार समझें, ऐसा नहीं है ।

अगर उस समझौते की लाईन पर ही हम चलें, तो बहुत कुछ सद्भावना वातावरण बन सकता है ।

दूसरी बात, जो विदेशों में भारत विरोधी प्रचार लगातार करते जा रहे हैं, उसको बन्द करना चाहिये । हमेशा, विदेशों से अगर उनको सहायता लेनी होती है, तो भारत को एक हौव्वा बना कर खड़ा कर देते हैं कि इतना बड़ा मुल्क है, हमें उससे डर है, हमें इतनी मदद चाहिये । और साम्राज्यवादी जाने क्या-क्या कहते रहते हैं ।

तीसरा, आतंकवादियों को तो खुलेआम यह सहायता देते ही हैं, तस्करी को भी बढ़ावा देते हैं । हमारे देश में तस्करी को भी बढ़ावा देते हैं, हथियार भी देते हैं । अपने यहां तमाम प्रशिक्षण केन्द्र लगा रखे हैं । आतंकवादी वहां जायें, उनको बाकायदा सब कुछ सहायता मिलेगी, हथियार और सहायता देते है और फिर यहां भारत में तोड़फोड़ करने के लिये भेज देते हैं । तो यह सब बातें बन्द होनी चाहिये ।

चौथा, जो हमारे राजनयिक है– पिछले दिनों राजनयिकों पर हमले हुये उसे भारत कभी भुला नहीं सकता । भारत के देशवासी कभी भुला नहीं सकते कि इस तरह से राजनयिकों पर झूठे और बेबुनियाद जासूसी के आरोप गा कर उन्हें शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया जाता है । वह बन्द होना चाहिये । और भविष्य में ऐसा कभी नहीं होना चाहिये । यह बात सुनिश्चित करनी चाहिये ।

पांचवें, मैं बहुत संक्षेप में एक बात कहना चाहती हूं कि भारतीय सैनिक जो पिछली कुछ लड़ाइयों में लापता थे और कई बार अखबारों में आया है कि वहां पर कुछ भारतीय सैनिक बंदी हैं, जिनके बारे में उन्होंने तो कोई सूचना शायद भारत सरकार को नहीं दी है कि वहां पर कुछ सैनिक बंदी हैं, उनके बारे में भी जानकारी मिलनी चाहिये । बातचीत में इस मुद्दे को भी रखा जाना चाहिये ।

इसके साथ ही अफज़ल साहब ने अभी कहा कि भारत से संबंध हैं–मैं तो कहती हूं कि रिश्तेदारियां ही नहीं, आधे परिवार उधर हैं, और आधे इधर हैं । बहुत से लोग यहां से जाते हैं– हमारी तो बड़ी अच्छी सद्भावना की प्रवृत्ति है । भारत ने कभी भी तंग करने की भावना से किसी से व्यवहार नहीं किया है । लेकिन यह निश्चित है कि हमारे देश के जो नागरिक यहां से अपने सगे-संबंधियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई-बंधुओं से मिलने के लिये जाते हैं, वह बड़ा एक कड़वा अनुभव लेकर के आते हैं ।

वहां सीमा पर उनको जासूस की नजर से देखा जाता है । शायद बूढ़े लोगों, बूढ़ी महिलाओं तक यह समझा जाता है कि जाने कहां से यह दूसरी श्रेणी के आ गये हमारे यहां दुश्मनों के देश से । तो उनके पास सभी वैध कागजात और वीजा वगैरह, सब कुछ होता है, फिर भी उनको भी पकिस्तान सीमा पर तंग किया जाता है । उनके अधिकारी तंग करते ही हैं, उनका सामान भी छीन लेते हैं । गरीब आदमियों ने, महिलाओं ने भी बताया कि हम यहां से कुछ नहीं, तो वहां पर पान बहुत मंहगा मिलता है, पान थोड़ा सा लेकर जाते हैं कि दस-पन्द्रह दिन वहां रहेंगे, लेकिन वह तक भी छीन लेते हैं ।

एक-दो लोगों से तो पैसे भी छीन लिये और उनके पास घर पहुंचने तक के लिये किराया भी नहीं छोड़ा तो भारतीय अधिकारियों ने उनको किराया दिया, उनके घर आने की व्यवस्था की ।

इन सभी बातों की तरफ माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे और इस वार्ता में इन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे । धन्यवाद ।

[7.00 P.M.]

श्री आर० एल० भाटिया : मैडम, कृष्ण लाल जी ने, मालवीय जी ने, जगमोहन जी ने, कमला जी ने और जार्ज जी ने जो मुद्दे उठाये हैं वे तकरीबन मिलते-जुलते हैं । सब से पहले बात यह है कि हम यह बातचीत करने क्यों जा रहे हैं, इसका क्या फायदा होगा । पीछे भी इतनी बार बात हुई है, लेकिन उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया । एक प्रश्न यह सामने आ रहा है । मैं इतना ही कहूंगा इसके बारे में सेकि हमारी एक पालिसी है कि उनसे बात-चीत के जरिये मसले का हल किया जाय और उसी के पश्चात हम उनसे बात-चीत करते हैं । बात-चीत करने से यह बात ठीक है कि जो हम चाहते हैं वह सारी बातें सामने नहीं आती हैं, लेकिन उसका नतीजा कुछ तो निकलता है । जैसे पिछली टाक्स में से हमने दो एग्रीमेंट्स उनसे किये हैं । एक यह कि जब भी हम एक दूसरे मुल्कों में, अपने दोनों मुल्कों में एक्सरसाइजेज करें, मिलिट्री एक्सरसाइजेज करें, उनकी दोनों मुल्क एक-दूसरे को चेतावनी दें । दूसरा फैसला यह हुआ कि जब भी हमारे जहाज मिलिट्री के जहाज उधर जायें हवाई जहाज या इनके जायें उनके बारे में भी हमें एक दूसरे से यह बात का भी एग्रीमेंट हुआ है कि वह नहीं जाने चाहियें । इसके अलावा जितने भी मुद्दे हैं, जो मेरे सारे साथियों ने, आनरेबल मैंबर्ज ने उठाये हैं, ये सारी बातें हम उनको उन मीटिंग्स में कहते रहते हैं और जोर से कहते हैं और हिन्दुस्तान का जो मुअक्कफ है उसको हम बड़े जोर से कहते हैं । उसमें कोई ढील नहीं होती, उसमें कोई कमी नहीं होती । लेकिन यह हमारा ख्याल ही नहीं बल्कि अकीदा है कि यह मसला दोनों मुल्कों का बात-चीत के जरिये ही हल होगा । आज हो, कल हो, कब हो । तो इसके अलावा कोई आल्टरनेटिव है भी नहीं । इसलिये हम बात-चीत करते रहते हैं । दूसरी बात यह कही गई कि पाकिस्तान बात-चीत को एक कवर समझता है जगमोहन जी ने कहा, लेकिन जो उनका मुद्दा होता है वह करते जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वह जो बातें हम से करते हैं तो ग्राउंड लैवल पर उसका असर वह हम नहीं देखते हैं इसमें कोई शक वाली बात नहीं है

आपने डायलिंग की बात की । यह हमारा पाकिस्तान के साथ डाइरेक्ट डायलिंग का एग्रीमेंट है । वहां से वह उनको फैसिलिटी पी०ओ०के० में देते हैं । इसका हमारा डायरेक्टर कोई सिलसिला नहीं है । उधर से हो तो हो सकता है । तीसरी बात यह कही गई कि पाकिस्तान बाहर बहुत प्रोपेगंडा कर रहा है और उसके मुकाबले में हिन्दुस्तान प्रोपेगंडा नहीं करता । मैं इस बात को ऐसा नहीं मानता । हमने काफी इस बात पर तवज्जह दी है और हमारी जो एक्सटर्नल पब्लिसिटी डिवीजन है, उसने गलत लिटरेचर छाप कर दूसरे मिशंस को भेजा है और बाहर हम सब जगह भेजते हैं जहां हम जरूरी समझते हैं चाहे वह लायब्रेरीज हैं, चाहे दूसरे लोग हैं और इसमें कोई ढील नहीं है । वह बाकायदा प्रोपेगंडा हम भी कर रहे हैं और पूरे जोर से कर रहे हैं । दूसरी बात यह है कि हमारे जो मिशंस बाहर हैं वह भी इस बात पर विजिलेंट हैं । वह देखते हैं कि पाकिस्तान का प्रोपेगंडा किस तरह, किस शक्ल में हो रहा है और वह उसी शक्ल में उसका जवाब दे रहे हैं । तीसरी बात यह है कि हमने बहुत आर्टिकल इस बात पर तैयार किये हैं, हमारे बहुत से अखबार वालों ने भी इस पर चर्चा की है और वह भी बाहर से भेजे जाते हैं ताकि पब्लिक ओपीनियम को हम उसका जो प्रोपेगंडा है उसका जो असर है, वह होने पाये । इस बात का मैं एक

आपको सबूत देना चाहता हूं कि इसमें डील नहीं है । हमारा प्रोपेगंडा है । हमने वर्ल्ड पब्लिक ओपीनियन को जागृत किया है जो पाकिस्तान काश्मीर और पंजाब में कर रहा है । उसके फलस्वरूप अब आपके सामने है कि अमरीका में जो फारेन एफेयर्ज की रिपोर्ट छपती है उसमें उन्होंने लिखा है :

On Pakistan's support to terrorism directed against India, the U.S. State Department in its Annual Report on Patterns of Gobal Terrorism in 1991 issued on 5th May, 1992, has stated that there was continued credible report throughout 1990-91 of official Pakistan's support for Kashmir militant groups engaged in terrorism in Kashmir as well as support to the Sikh terrorists in Punjab.

इसी तरह ब्रिटिश होम सेक्रेटरी मिस्टर केनेथ बेकर ने हिन्दुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू दिया 04 जनवरी, 1991 को; उसमें उन्होंने बताया कि--

"The Pakistan Government is fully aware of our concern that material support is reaching terrorists in Kashmir and Punjab from the territories controlled by Pakistan."

इस तरह बहुत से मुल्कों की भरे पास खबर है और यह तभी हुआ है जब हमने उनका प्रोपेगंडा काउंटर किया है दूसरे डेशों में और तभी उन गवर्नमेंटस ने महसूस किया है कि भारत ठीक है और पाकिस्तान गलत है । तो यह कहना कि हिन्दुस्तान की ओर से काउंटर प्रोपेगंडा नहीं किया गया, यह बात ठीक नहीं होगी ।

मिस्टर फर्नांडिस ने कहा कि ए०के० 47 वगैरह पाकिस्तान में नहीं बनती । तो वह तो दुनियां में ओपन मार्केट में कोई भी ले सकता है । गवर्नमेंट तो डील करती है, लेकिन प्राइवेट आम सारी दुनियां में यह मिल जाते हैं । एक भाई ने कहा कि पाकिस्तान का एटीट्यूड जो हिन्दुस्तानियों की तरफ है वह ठीक नहीं है । जब वहां लोग जाते हैं तो उनको तंग करते हैं, उनको कस्टम वाले तंग करते हैं, पासपोर्ट वगैरह की दिक्कत होती है, वगैरह-वगैरह । यह जो बातचीत हो रही है, उसमें यह हमारे एजेंडा का एक हिस्सा है क्योंकि इसके बारे में हमें शिकायतें मिल चुकी हैं ।

एक माननीय सदस्य : वीसा की भी । **(व्यवधान)**

श्री आर०एल० भाटिया : सारी बातें उसमें आयेंगी ।

सत्या बहिन ने दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाये हैं । पहला तो यह कि आया, पाकिस्तान से जो हमारा शिमला एग्रीमेंट हुआ है उसको वह मानते हैं या नहीं मानते ? यह एग्रीमेंट हुआ है, उसी के आधार पर हम यह बातचीत कर रहे हैं । तो न मानने का सवाल नहीं उठता । दूसरा जो आपने डिफेंस पर्सोनेल का कहा । तो, मैडम, पाकिस्तान में हमारे 54 डिफेंस पर्सोनेल उनके पास हैं । जब भी चर्चा हुई, जब भी बातचीत हुई, हमने सवाल उठाया तो उन्होंने इस बात से इंकार किया है कि उनके पास हमारे कोई डिफेंस पर्सोनेल है । लेकिन, उसके बावजूद भी हमारी कोशिश जारी है । हम बार-बार यह बात कह रहे हैं । पाकिस्तान वालों ने जो पीछे मीटिंग्स हुई थी, उसमें यहां तक कह दिया कि भाई, आपको अगर भरोसा नहीं तो आप हमारी जेलें आकर देख सकते हो । वह जो 54 डिफेंस पर्सोनेल हैं, उनके पेरेंटस, रिश्तेदार जो हैं, हमने उनको पाकिस्तान भेजा । उनको वहां की जेल दिखा दी । उनके रिश्तेदार वहां मिले नहीं । लेकिन, उसके बावजूद भी हमें शक है कि यह आदमी उनके पास जरूर होंगे । उसके लिये हम कोशिश कर रहे हैं और इस बातचीत में यह हमारा हिस्सा है । तो मैं यही कहूंगा कि यह हमारी पालिसी है

It is our policy to continue to keep the channels of communication open with Pakistan and try to solve all the issues peacefully through bliateral negotiations. In our view, dialogue is essential to keep tension under control.

बाकी, कश्मीर के बारे में बहुत चर्चा हुई है कि कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यह कह रहा है, वह कहा है या नवाज शरीफ ने यह यह स्टेटमेंट दीं । वह सब बातें अखबारों में आई है । उससे हम इंकार नहीं करते, लेकिन एक बात मैं आपको साफ कह देना चाहता हूं कि—

Kashmir is an intgeral part of India and no compromise will be effected to the integrity and unity of India.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, I don't generally comment on the discussions from the Chair. But on this issue, I would like to tell you one thing that we started our proponganda about Kashmir much late. That is why now we are getting the result. We should have started it 40 years, 45 years, ago because they never stopped propogating about Kashmir and we started it much later. This is my comment.

MESSAGES FROM THE LOK SABHA

(I) The Jammu and Kashmir Appropriation (No. 2) Bill, 1992.

(II) The Appropriation (No. 3) Bill, 1992.

(III) The Appropriation (No. 4) Bill, 1992.

(IV) The Special Court (Trial of Offences Relating to Transactions in Securities) Bill, 1992.

THE SECRETARY GENERAL: Madam, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary General of the Lok Sabha.

(II)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha I am directed to enclose the Jammu and Kashmir Appropriation (No. 2) Bill, 1992, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 11th August, 1992.

2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill."

(II)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in in Lok Sabha, I am directed to enclose the Appropriation (No. 3) Bill, 1992 ,as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 12th August, 1992.

2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

(III)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in in Lok Sabha, I am directed to encolse the Appropraition (No. 4) Bill, 1992 ,as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 12th August, 1992.

2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

(IV

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in in Lok Sabha, I am directed to enclose the Special Court (Trial of Offences Relating to Transactions in Securities) Bill, 1992, as passed by Lok Sabha at its sitting held on 12th August, 1992."

Madam, I lay a copy of each of the Bills on the Table.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned till 11 a.m. on Monday, the 17th August, 1992.

The House then adjourned at twelve minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Monday, the 17th August, 1992.